चीनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उपलब्ध है। इसके विपरीत लगभग 48 लाख टन की वर्तमान आवश्यकता है।

(ग) चीनी की वर्ष 1 अक्तूबर, 1995 से 30 सितम्बर, 1996 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु चीनी के आयात का कोई भी अनुबंध एस०टी०सी० तथा एम०एम०टी०सी० द्वारा नहीं किया गया है।

छोटे और कुटीर उद्योग

873. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में स्थित छोटे और कुटीर उद्योगों को केन्द्रीय सरकार के उदासीन रवैये के कारण समुचित रूप से विकसित नहीं किया जा रहा है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में छोटे और कुटीर उद्योगों का कुल उत्पादन कितना था और इस अवधि के दौरान इन उद्योगों में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या कितनी थी; और

(ग) देश में छोटे और कुटीर उद्योगों के विकास हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये हैं और पिछले तीन वर्षों में इन उद्योगों के विकास के लिये कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गयी है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, नहीं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान लघु क्षेत्र और खादी और ग्रामीण उद्योगों में उत्पादन और रोजगार के अनुमान इस प्रकार हैं:—

	लघु उद्योग		खादी और ग्रामीण उद्योग	
वर्ष	उत्पादन	रोजगार	उत्पादन	रोजगार
	(वर्तमान मूल्यों पर) (करोड़ रु० में)	(लाख संख्या में)	(करोड़ रु० में)	(लाख संख्या में)
1993-94	241648	139.38	3233.86	53.28
1994-95	293990	146.56	3624.06	53.46
1995-96 (अ)	316421	152.61	4470.00	60.50

(अ) अनुमानित

(ग) केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं:—

(1) उद्यमिता विकास (2) निरीक्षण, मार्गदर्शन, कार्यशाला, परीक्षण, टूल रूम और उत्पाद एवं प्रक्रिया विकास संबंधी सुविधाओं के द्वारा तकनीकी सहायता (3) मूल्य और क्रय वरीयता के जरिये और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और राज्य लघु उद्योग विकास निगम द्वारा विपणन सहायता (4) विकसित औद्योगिक भूखण्डों, शैडों इत्यादि के जरिये राज्य सरकारों द्वारा अवसंरचनात्मक सहायता (5) वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तीय और पूंजी संबंधी सहायता।

पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित केन्द्रीय क्षेत्र योजना संबंधी परिव्यय उपलब्ध करवाया गया है:—

(करोड़ रुपये)

	1993-94 वास्तविक	1994-95 वास्तविक	1995-96 बजट अनुमान
लघु उद्योग (सीडो + एन०एस०-आई०सी०)	155.95	205.81	250.60
खादी और ग्रामोद्योग आयोग	195.50	205.00	343.00

Privatisation of Coal Mines

874. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether Government have decided to privatise coal mines;

(b) if so, the action taken so far in this direction; and

(c) the details thereof?